जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 83 प्रभात बीकानेर, बुधवार 15 अक्टूबर, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

जैसलमेर -जोधपुर हाईवे पर स्लीपर बस में आग लगी, 12 की मौत

मुख्यमंत्री जैसलमेर पहुँचे, बस में सवार 57 यात्रियों में अधिकतर 70 प्रतिशत तक झुलसे

जैसलमेर/जोधपुर, 14 अक्टूबर (नि.सं.)। जैसलमेर में जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर चलती एसी स्लीपर बस में आग लग गई। आग ने भीषण रूप ले लिया। बचने के लिए यात्री चलती बस से कूद गए। हादसे में 12 लोगों की मृत्यु होने के समाचार हैं। झुलसे यात्रियों को तीन एंबुलेंस से जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से सभी को जोधपुर रैफर कर दिया। अधिकांश यात्री 70 प्रतिशत तक झुलसे हैं।

जैसलमेर पहुंच कर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना को लेकर जिला प्रशासन से फीडबैक लिया।

जानकारी के अनुसार, बस में 57 लोग सवार थे। नगरपरिषद के असिस्टेंट फायर ऑफिसर कृष्णपालसिंह राठौड़ ने हादसे में 12 लोगों की जलने से मौत होने के समाचार दिये हैं। आग लगने का कारण बस की एसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

बस में आग लगने का हादसा जैसलमेर के थईयात गांव के पास हुआ। आग की लपटें और धुआं काफी ऊंचाई

- **बस में आग लगने का कारण ए.सी. में शार्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। गंभीर रुप से झुलसे लोगों के लिये जोधपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया।**

तक उठता रहा। बस रोजाना की तरह दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी। करीब 20 किलोमीटर दूर रास्ते में थईयात गांव के पास अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग ने पूरी गाडी को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की सूचना मिलते ही, आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे तथा राहत कार्य शुरू किया। लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। झुलसे यात्रियों को तीन एंबुलेंस से

(शेष पृष्ठ 4 पर)

जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर थईयात गांव के पास मंगलवार दोपहर एसी स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई।

प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर अभी भी सस्पैंस बरकरार

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (जेएसपी) ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें 65 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लेकिन इस सूची में स्वयं प्रशांत किशोर का नाम नहीं है।

पिछले सप्ताह जेएसपी ने पहली सूची जारी की थी, जिसमें 51

- **जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में भी पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर का नाम नहीं है।**

उम्मीदवारों के नाम थे। इस तरह पार्टी ने अब तक कुल 116 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिनमें से 26 सीटें आरक्षित (25 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति) के लिए हैं, जबकि 90 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं।

जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों की इस सूची में बिहार के कई जिलों जैसे पटना, मधुबनी, गोपालगंज, वैशाली, नवादा और समस्तीपुर, के नाम शामिल हैं। 21 उम्मीदवारों में प्रमुख नाम हैं, संजय यादव (मधेपुरा), तौरीफरहमान (नरकटियागंज), रवि राज कुमार (हिसुआ), पुष्पा कुमारी (बनियापुर), एडवोकेट मीनू कुमारी (पटना

(शेष पृष्ठ 4 पर)

'तुम लोगों ने कैसे स्वीकार कर लिया सीटों के बंटवारे का फार्मूला'

नीतीश कुमार अपनी पार्टी के उन नेताओं से अति कुपित हैं जिन्होंने भाजपा से सीटों के बँटवारे को स्वीकृति दी थी

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। बिहार में एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) में उथल-पुथल मची हुई है। जेडीयू नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीट बंटवारे के समझौते पर दोबारा बातचीत करने पर अड़े हुए हैं। वहीं, गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों - हम (हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा) के प्रमुख जीतन राम मांझी और आर एल एम (राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मंच) के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा - ने भी असंतोष जताया है।

सोमवार को भाजपा द्वारा घोषित सीट बँटवारे के समझौते के अनुसार, 243 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा और जेडीयू दोनों को 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। चिराग पासवान के नेतृत्व वाले लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें, तथा हम और आर एल एम को 6-6 सीटें मिली हैं।

सोमवार शाम अपने आवास पर बुलाई गई आपात बैठक में मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के समझौता वार्ताकारों - संजय झा, राजीव रंजन सिंह 'लल्लन', और विजय चौधरी को फटकार

- **नीतीश ने धमकी दी कि न तो वे स्वयं न उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होगा जब तक सीट बँटवारे का फार्मूला नहीं खुलेगा और दुरुस्त किया जायेगा।**
- **नीतीश कुमार भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं से यह पक्की व साफ घोषणा चाहते हैं कि अगर एनडीए मिलकर पुनः सरकार बनाती है तो नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे।**
- **नीतीश ने साफ कहा, कि भाजपा का गोलमोल आश्वासन, कि एनडीए नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है, पर्याप्त नहीं है और उन्हें स्वीकार नहीं है।**
- **भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्रीय सरकार पर कुप्रभाव पड़ता है अगर बिहार का चुनाव एनडीए के खिलाफ गया, अतः भाजपा भी सीटों के बँटवारे को नीतीश की शर्त के अनुसार दोबारा खोलने को तैयार हो जायेगी।**

लगाई। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बात से नाराज़ हैं कि उनकी टीम ने भाजपा के साथ बराबर की सीटें स्वीकार कर लीं और साथ ही कुछ पारंपरिक जेडीयू सीटें भाजपा या लोजपा (रामविलास) को सौंप दीं। उदाहरण के लिए, भाजपा ने मुँगेर ज़िले की तारापुर सीट से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि यह सीट 2010 से जेडीयू के कब्जे में थी। चौधरी का नाम भाजपा की मंगलवार को जारी 71 उम्मीदवारों की सूची में शामिल है।

सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक समझौते पर दोबारा बातचीत नहीं होती, वे किसी भी एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस में न तो खुद

(शेष पृष्ठ 4 पर)

आईएमएफ भारत की इकॉनमी की बढ़ाइयों के पुल बांध रहा है

आईएमएफ के अनुसार यूरोप के देशों की इकॉनमी की हालत काफी खस्ता होने वाली है भारत की तुलना में

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। वॉशिंगटन में फंड-बैंक की छमाही बैठक शुरू होने के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी "वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक" रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बेहद सकारात्मक तस्वीर पेश की गई है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अब भारत की आर्थिक संभावनाओं की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि, कहा जा रहा है कि भारत की यह जोरदार प्रशंसा इन संस्थानों के प्रति भारत की उदारता को दर्शाती है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अब तक इन संस्थानों को सबसे ज्यादा धन राशि देता था, उसने अपने योगदान में कटौती कर दी है।

हर साल ये दोनों प्रमुख संस्थान, आईएमएफ और विश्व बैंक, दो बैठकें करते हैं, एक शरद ऋतु में और दूसरी

- **यूरोपीय देशों की इकॉनमी, उनका व्यापार व उद्योग सदा से ही अमेरिकी बाजार व मांग पर आश्रित रहा है।**
- **पर भारत की इकॉनमी की ताकत है देश की स्वयं की मांग। अतः अमेरिकी टैरिफ का यहां उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।**
- **आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में स्वीकार किया है कि विकसित देशों की इकॉनमी निगेटिव रह सकती है, जिसमें अमेरिका शामिल है।**
- **आईएमएफ के आंकलन के अनुसार एशिया की इकॉनमी इतनी खराब नहीं होगी, और एशिया में सबसे सुदृढ़ इकॉनमी भारत की रहेगी।**

वसंत ऋतु में। मौजूदा बैठक का उद्देश्य मौजूदा खतरों और अवसरों की समीक्षा करना है।

आईएमएफ ने भारत की 2025 की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि अगले वर्ष, यानी 2026 के लिए अनुमान 6.2 प्रतिशत रखा गया है, क्योंकि अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर ऊंचे शुल्क लगा दिए हैं।

इस मामूली गिरावट के बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने

(शेष पृष्ठ 4 पर)

हाई कोर्ट के दो न्यायाधीश दिल्ली गये, एक जयपुर आये

जयपुर, 14 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों का तबादला किया गया है, इनके अलावा एक न्यायाधीश को वापस राजस्थान

- **राजस्थान से जस्टिस दिनेश मेहता व अवनीश झिंगन दिल्ली हाई कोर्ट गये तथा वहां के जस्टिस अरुण मोंगा का राजस्थान तबादला हो गया।**

हाईकोर्ट भेजा गया है।

केन्द्र सरकार ने तीन अलग-अलग आदेश जारी कर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता और अवनीश झिंगन का दिल्ली हाईकोर्ट तबादला किया है। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत जस्टिस अरुण मोंगा का तबादला कर राजस्थान हाईकोर्ट भेजा गया है। जस्टिस मोंगा का गत जुलाई माह में राजस्थान हाईकोर्ट से दिल्ली तबादला किया गया था।

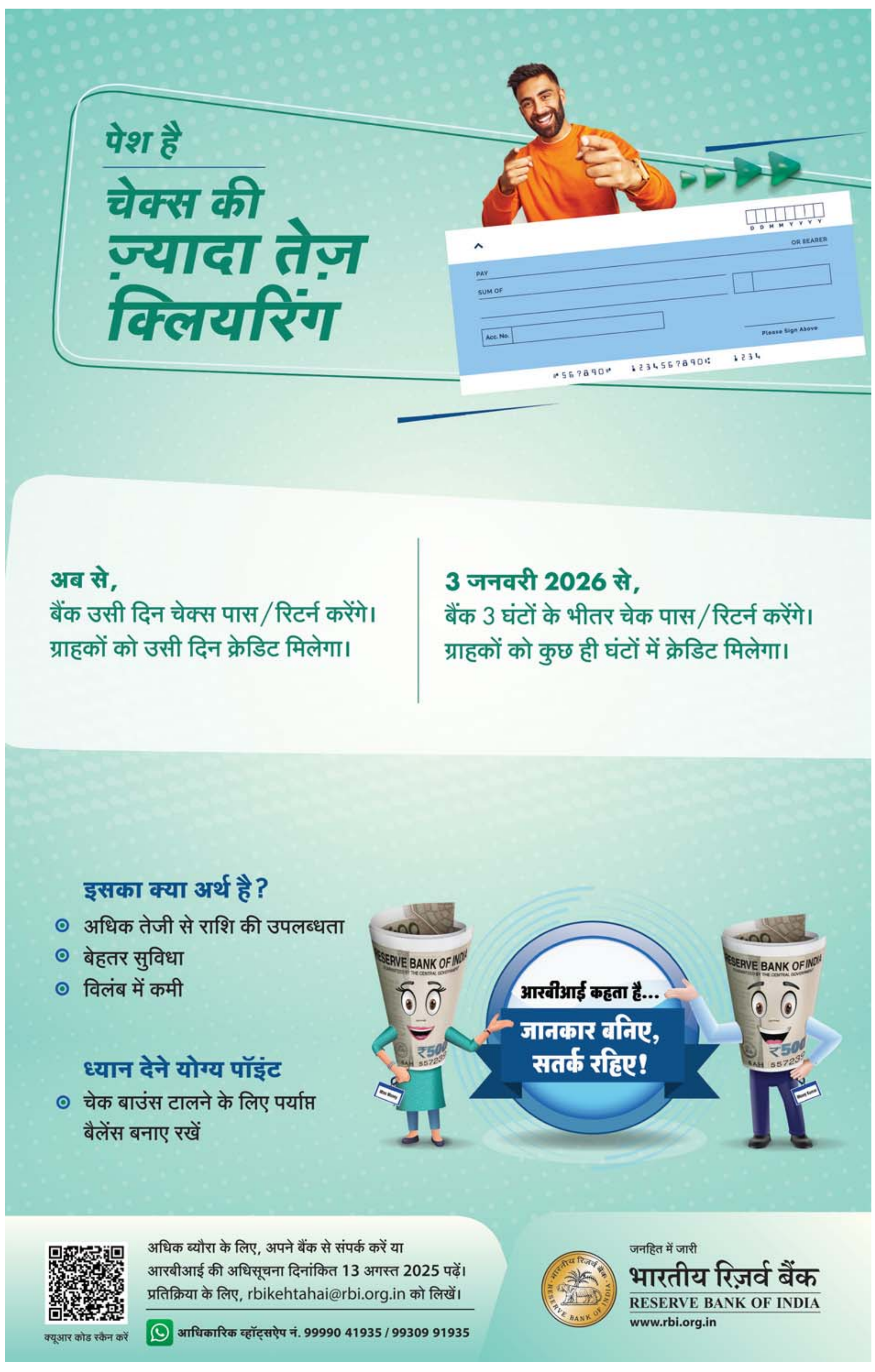

मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, ओ.बी.सी. कोटा अपने राज्य में बढ़ाने के लिये कई दलीलें, पंद्रह हज़ार पन्नों के शपथ पत्र के माध्यम से दीं

शपथ पत्र में सरकार ने अंबेडकर सोशल साइंस यूनिवर्सिटी (मऊ) के एक अध्ययन व शोध पत्र को कई बार उद्धृत किया।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल मध्य प्रदेश सरकार के हलफ़नामे की शुरुआत ही एक विरोधाभास से होती है। दस्तावेज़ में प्राचीन भारत को एक जातिहीन, योग्यता-आधारित समाज के रूप में गौरवान्वित किया गया है और विदेशी आक्रमणों को सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव लाने के लिए दोषी ठहराया गया है। यह वैदिक काल को समानता और सौहार्द का युग बताता है, लेकिन बाद में भारत की आर्थिक गिरावट का कारण किसानों और कारीगरों के जाति-आधारित शोषण को बताता है एक ऐसा अन्याय, जिसे पहले इसने अस्तित्वहीन बताया था।

- **मध्यप्रदेश सरकार ओबीसी कोटा को चौदह से सत्ताईस प्रतिशत करना चाहती है।**
- **यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण, पचास प्रतिशत की सीमा लांघ कर तिरेसठ प्रतिशत हो जाती है।**
- **अंबेडकर यूनिवर्सिटी के सर्वे में कई उदाहरण अंकित हैं, जिनमें मध्यप्रदेश में ओबीसी के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार व अपमानजनक प्रथाओं का विस्तार से विवरण दिया है।**

यही विरोधाभास राज्य में ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की सरकार की कानूनी दलील की नींव बनता है। इस दलील को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे और राष्ट्र-निर्माण के भाषण में लपेटा गया है।

इस रिपोर्ट की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में जातिगत भेदभाव की बार-बार सामने आने वाली घटनाएँ हैं। हाल की एक घटना में दमोह में ओबीसी कुशवाहा समुदाय के एक युवक को एआई से बनाई गई तस्वीर के विवाद के चलते एक ब्राह्मण व्यक्ति के पैर धोने के लिए मजबूर किया गया।

राज्य सरकार के 15,000 पन्नों के हलफ़नामे से पता चलता है कि ऐसी घटनाएँ अपवाद नहीं हैं। हलफ़नामे में न केवल मध्य प्रदेश में जाति-आधारित भेदभाव होने को स्वीकार किया गया है, बल्कि व्यापक संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश भी की गई है, जिनमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण और लाड़ली बहना व लाड़ली बेटी जैसी कल्याणकारी योजनाओं में ओबीसी महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत कोटा शामिल है।

सरकार के प्रस्तुतिकरण में डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू की एक गोपनीय

(शेष पृष्ठ 4 पर)